Explained: तांबा है भविष्य का तेल: वेदांता चेयरमैन के दावे में कितनी सच्चाई? भारत और दुनिया की स्थिति जानिए

Copper as future oil: क्या दुनिया को आने वाले वर्षों में तांबे की भारी किल्लत से जूझनी पड़ेगी? यह सवाल आज वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने उठाया और कहा कि तांबा ही भविष्य का तेल है।

Naveen Kumar Pandey

पब्लिश्ड 14 Oct 2026, 07:06 PM IST

Prefer Livemint on Google

Advertisement

OPEN IN APP



*वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल बोले- भविष्य में तांबा बनेगा तेल (AI Image)**(ChatGPT)***

वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में तांबा, नया तेल होगा। हालांकि, उन्होंने यह बात सवाल के रूप में कही है, लेकिन उनका ही दिया जवाब भविष्य की दिशा की ओर संकेत करता है। उन्होंने कहा कि तेल तो दुनियाभर में प्रचूर मात्रा में है, संकट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से है, लेकिन तांबा की उपलब्धता का ही संकट है। उन्होंने कहा, 'मांग के मामले में कॉपर नया तेल है, लेकिन आपूर्ति के मामले में स्थिति भयावह है।'

OPEN IN APP

फ्लिपबुक पर क्लिक कर पढ़ें वेदांता चेयरमैन का पूरा बयान



Original Post

Page 2 / 3

OPEN IN APP

s copper the next oil?

n terms of demand, yes. There will be an exponential rise with the spread of AI, data centres and aggressive electrification. In terms of supply, it may be different. The world has enough supply of oil. This can be disrupted by geopolitical events but fundamentally there is no global shortage. In copper, there is going to be a structural shortage which will keep rising over the

क्यों बढ़ रही है तांबे की मांग?

अग्रवाल के दावों का सारांश निकालें तो उन्होंने यही कहा है कि जिस प्रकार पेट्रोलियम ने 20वीं सदी के औद्योगिकीकरण और जियोपॉलिटिक्स को संचालित किया, उसी तरह तांबा 21वीं सदी के 'ऊर्जा संक्रमण' और 'डिजिटल क्रांति' की रीढ़ बनने जा रहा है। जरा इन तथ्यों पर गौर करें-

Advertisement

1. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल को प्रशिक्षित करने वाले सर्वर और डेटा सेंटर्स की बिजली खपत बहुत ज्यादा है। तांबा अपनी उच्च विद्युत चालकता के कारण डेटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर का प्राथमिक घटक है।

2. किसी पारंपरिक पेट्रोल या डीजल कार की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) में 3 से चार गुना अधिक तांबे का उपयोग होता है।

3. दुनिया में अक्षय ऊर्जा की उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। भारत सरकार पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता घटाने के लिए विभिन्न दिशाओं में उठाए गए कदमों के तहत सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन में भी बड़ी वृद्धि सुनिश्चित करना चाहती है। पवन ऊर्जा के लिए इस्तेमाल होने वाले टर्बाइन और सौर पैनल में काफी अधिक तांबे की आवश्यकता होती है।

OPEN IN APP

4. दुनिया भर में पावर ग्रिड के विस्तार और री-वायरिंग के लिए बड़े पैमाने पर तांबे के तारों की जरूरत है।

यह भी पढ़ें | निकल गई हेकड़ी? 21 दिन पहले कानून लाया था, अब खुद रूस से तेल खरीदेगा अमेरिका! ›

इतने बड़े पैमाने पर होगी तांबे की कमी?

अनिल अग्रवाल ने अपने पोस्ट में एक चार्ट भी शेयर किया जिसमें दर्शाया गया है कि कैसे अगले वर्ष 2027 से कॉपर की आपूर्ति में भारी कमी हो सकती है। चार्ट के अनुसार, 2035-2040 तक तांबा की किल्लत बढ़कर 10 से 12 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक के

तांबे को क्रिटिकल मिनरल घोषित कर रहे हैं देश

S&P ग्लोबल ने इस वर्ष की अपनी बेहद विस्तृत रिपोर्ट में वर्ष 2040 तक करीब 10 मिलियन टन के संभावित सालाना अंतर की आशंका जताई है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने भी 2035 तक मौजूदा घोषित परियोजनाओं के आधार पर लगभग 30% की संभावित कमी बताई है। यही वजह है कि पिचले पांच वर्षों से तांबा को क्रिटिकल मिनरल घोषित करने का सिलसिला चल पड़ा है। अमेरिका ने भी पिछले वर्ष 2025 में तांबा को क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में शामिल कर लिया।

भारत ने कॉपर को किस कैटिगरी में रखा?

भारत ने तांबो के 'क्रिटिकल एंड स्ट्रैटिजिक मिनरल' की सूची में शामिल नहीं किया, लेकिन इसे 'स्ट्रैटिजीक एंड डीप सीटेड' की सूची में रखा है। इसे ऐसे समझें। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज जो देश की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और आधुनिक तकनीक के लिए जरूरी हैं और जिनकी आपूर्ति बाधित होने का जोखिम है। महत्वपूर्ण और गहराई में पाए जाने वाले खनिज जिनके भंडार अक्सर जमीन की गहराई में होते हैं और जिनकी खोज तथा खनन के लिए उन्नत तकनीक और अधिक निवेश की जरूरत पड़ सकती है।

उत्पादन से आपूर्ति तक कौन, कितना आसान?

OPEN IN APP

अनिल अग्रवाल का कहना है कि तेल की सप्लाई में बाधाएं मुख्यतः भू-राजनीतिक हैं, जबकि तांबे की कमी संरचनात्मक हो सकती है। हालांकि, तेल की सप्लाई भी निवेश और पुराने क्षेत्रों में घटते उत्पादन पर निर्भर करती है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, पारंपरिक तेल क्षेत्रों में चरम उत्पादन के बाद गिरावट औसतन 5.6% सालाना है।

मौजूदा स्रोतों में निवेश बंद होने पर वैश्विक तेल उत्पादन अगले दशक में हर साल औसतन 55 लाख बैरल प्रतिदिन के बराबर घट सकता है। फर्क यह है कि तांबे की नई खदानों को विकसित करने में लंबा समय लगता है और घटती अयस्क गुणवत्ता भी सप्लाई बढ़ाने की चुनौती है।

दूसरी तरफ, एक नई तांबे की खदान की खोज से लेकर व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने में औसतन 10 से 16 साल लगते हैं। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के विश्लेषण में 2010-19 के दौरान शुरू हुई प्रमुख खदानों को खोज से व्यावसायिक उत्पादन तक पहुंचने में औसतन 16 साल से अधिक लगे। वहीं, S&P Global का हालिया विश्लेषण लगभग 17 साल का औसत बताता है।

यह भी पढ़ें | IT कंपनियों के ग्रीन कार्ड प्रोग्राम सस्पेंड होने का किस पर, क्या होगा असर?

तांबा उत्पादन में ये बड़ी चुनौतियां

चिली और पेरू जैसे प्रमुख तांबा उत्पादक देशों में मौजूदा खदानों से निकाले जाने वाले अयस्क में तांबे की सांद्रता (ग्रेड) लगातार कम हो रही है। ऊपर से पर्यावरणीय एवं सामाजिक चुनौतियां भी तांबा उत्पादन में आड़े आ रही हैं। जल संकट, खदानों के खिलाफ स्थानीय प्रदर्शन और सख्त ईएसजी मानकों के कारण नई खदानों की मंजूरी धीमी है।

6 सालइड्स में समझें तांबे का पूरा माजरा

OPEN IN APP



OPEN IN APP

तांबे की उपलब्धता को लेकर क्या है भारत की स्थिति?

वेदांता चेयरमैन के अनुसार, भारत अपनी जरूरत का 95% तांबा आयात करता है। यह भारत की 'महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा' के लिए बड़ा जोखिम है। उनका सुझाव है कि इस क्षेत्र में निवेश करना चाहिए। अग्रवाल ने कहा कि कॉपर के एक्सप्लोरेशन और माइनिंग में युवाओं को भी बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। भारत सरकार ने कॉपर सेक्टर के लिए

mint | हिन्दी



OPEN IN APP

वेदातां चेयरमैन का यह दावा कितना सही?

अनिल अग्रवाल का दावा है कि सही नीतियों और बेहतर जवाबदेही से भारत की मौजूदा कॉपर ऐसेट से उत्पादन कई गुना बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए कुछ आधार जरूर दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) ने वित्त वर्ष 2022-23 में 33.47 लाख टन तांबा-अयस्क का उत्पादन किया था। कंपनी ने अगले छह-सात

हालांकि, वित्त वर्ष 2024-25 में एचसीएल का वास्तविक अयस्क उत्पादन 34.74 लाख टन रहा, जो 2023-24 के 37.82 लाख टन से कम था। इससे स्पष्ट है कि उत्पादन बढ़ाने की संभावना और वास्तविक उत्पादन वृद्धि अलग-अलग बातें हैं। सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों के एक्सप्लोरेशन में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की व्यवस्था भी शुरू की है। लेकिन उपलब्ध आंकड़े अभी यह साबित नहीं करते कि भारत की मौजूदा कॉपर एसेट 10 गुना उत्पादन कर सकती हैं। इस दावे की पुष्टि के लिए खदान-वार भंडार, उत्पादन क्षमता, जरूरी निवेश और विस्तार योजनाओं का स्वतंत्र आकलन आवश्यक है।

क्या करे भारत ताकि तांबे पर तनिक भी न हो चिंता?

इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत के पास तांबे के एक्सप्लोरेशन और प्रॉडक्शन को बढ़ाने का बड़ा अवसर है। देश के कई क्षेत्रों में गहराई से भूगर्भीय सर्वेक्षण और खनिजों की खोज की गुंजाइश है। इसके लिए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के तर्ज पर निजी क्षेत्र, विशेषकर छोटी अन्वेषण कंपनियों को प्रोत्साहित करने, जोखिम पूंजी उपलब्ध कराने और युवाओं को भूविज्ञान एवं खनन तकनीक से जुड़े अवसर देने की जरूरत है।

साथ ही, मौजूदा खदानों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक, परिचालन दक्षता और पारदर्शी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर जोर देना होगा। इसके अलावा, तांबे को उसके गुणों में उल्लेखनीय कमी के बिना बार-बार रीसायकल किया जा सकता है। इसलिए भारत को कॉपर स्क्रैप के कलेक्शन, सॉर्टिंग और रीसाइकलिंग की व्यवस्थ मजबूत करके तथा अनौपचारिक क्षेत्र को संगठित प्रणाली से जोड़कर घरेलू आपूर्ति बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए।

OPEN IN APP

यह भी पढ़ें | कैलिब्रेटेड टाइटनिंग... 8 साल बाद RBI ने कही यह बात, निवेशकों के लिए क्या मायने? ›

जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की ओर बढ़ती दुनिया

अंत में यही कहा जा सकता है कि यह जियो इकोनॉमिक्स का नया दौर है। जैसे 20वीं सदी में तेल के स्रोत पर नियंत्रण रखने वाले देशों का वैश्विक वर्चस्व था, 21वीं सदी में तांबा, लिथियम और कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स पर नियंत्रण रखने वाले राष्ट्र ही आर्थिक और तकनीकी शक्ति बनेंगे। भारत को ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए 'क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी' में तत्काल और निर्णायक कदम उठाने होंगे।